

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या-50/2024

1. जयप्रकाश पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मांगीराम पुत्र रामजस जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. श्रवण पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. अधिशाषी अभियन्ता (XEN) सार्वजनिक निर्माण विभाग, नोहर तहसील नोहर।
2. तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर तहसील नोहर

—रेस्पोंडेन्टस



उपस्थित:— श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांत।

निर्णय

दिनांक:— 19/03/2024

अपीलांत जयप्रकाश पुत्र देवीलाल जाति जाट, मांगीराम पुत्र रामजस जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर द्वारा नामान्तरण आदेश सं. 663 स्वीकृति दिनांक 20.11.2009 रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर अपारस्त किये जाने हेतु अपील अपीलान्ट निम्न प्रकार से है—

1. रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के ख.न. 444 की 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि गै. मु. आबादी भूमि थी तथा सघन आबादी भूमि में ग्राम वासियों पक्के मकान निर्मित थे तथा ख0नं0 435 में भी आबादी बसी हुई है तथा केन्द्र सरकार की अनुमती के बिना सड़क निर्मित करना संभव नहीं है। उनके पक्ष में पटटे जारी कर रखे थे तथा सैकड़ों वर्षों की रिहायश थी। रेस्पोंडेन्टस ने रेस्पोंडेन्ट सं. 1 के पक्ष में बिना की जाँच किये ग्राम पंचायत को बिना सुने ग्राम पंचायत की एन.ओ.सी. लिये बिना ही गैर कानूनी ढंग से अपीलाधीन नामान्तरण आदेश पारित किया है, जो अपारस्तनीय है।
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क की भूमि अवाप्त किये जाने से पूर्व आबादी का कोई सर्वे नहीं कराया गया मौके पर मातहत अदालत ने भी सर्वे नहीं किया सघन आबादी जिसमें लोगो के निर्मित घर थे पर गै.मु. सड़क का अपीलाधीन नामान्तरण कतई गलत तौर से किया है, जो अपारस्तनीय है।

3. मातहत अदालत ने अपीलाधीन नामान्तरण आदेश से पूर्व किसी भी पक्षकार को कोई नोटिस नहीं दिया यहा तक सरपंच ग्राम पंचायत गोरखाना को आबादी भूमि में गै.मु. सड़क दर्ज किये जाने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया तथा गै. मु. सड़क की भूमि का नामान्तरण दर्ज किया उस जगह सधन आबादी थी सामान्य नागरिकों के पक्के मकान निर्मित थे उनके पक्ष में ग्राम पंचायत गोरखाना द्वारा पट्टे जारी थे। मातहत अदालत ने बिना नोटिस दिये साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही गैर कानूनी ढंग एवं नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि स्दक Acquisition Act 1894 की धारा 4 व 5 ए व 6 के तहत राज्य सरकार को भू-अर्जन कलैक्टर की रिपोर्ट पर कोई विचार नहीं किया इसलिए अर्जन की अधिसूचना रद्द योग्य थी तथा धारा 4 व 6 के तहत आबादी में स्थित बसे नागरिकों को कोई नोटिस नहीं दिया भूमि अर्जन की कोई सूचना नहीं थी अपीलान्त व अन्य नागरिकों के पट्टे बने हुए थे वैध स्वामी भूमि अर्जन से मुक्त करवाने का अधिकार रखता है इसके अतिरिक्त धारा 9 भूमि अर्जन अधिनियम के तहत अवाप्ति से पूर्व अपीलान्त व पट्टे धारियों को कोई नोटिस नहीं दिया तथा भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु नहीं था। पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता अधिनियम सन् 2013 की धारा 24 किसी भी पट्टे धारा निर्मित मकान के मालिक को उचित प्रतिकर नहीं दिया भूमि की रिपोर्ट तक नहीं देनी मौका नहीं देखा इसलिए उक्त अवाप्ति लोक प्रयोजन हेतु नहीं मानी जा सकती है इस परिस्थितियों अपीलाधीन नामान्तरण गैर कानूनी ढंग से पारित है जो अपास्तनीय है।
5. मातहत अदालत ने अपीलाधीन नामान्तरण करने से पूर्व कोई पैमाईश नहीं की तथा मकान आदि जो निर्मित भवन थे, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं की तथा वाद स्थल का कोई मौका निरीक्षण नहीं किया तथा पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य व जवाब प्रस्तुति का कोई समुचित अवसर नहीं दिया अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किये जाने की पट्टे व मकान मालिकों को कोई सूचना नहीं थी भूमि के पट्टे सिविल कोर्ट से निरस्त कराये वगैर अपीलाधीन नामान्तरण गैर कानूनी ढंग से दर्ज किया गया है, जो अपास्तनीय है।
6. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.11.2009 आदेश स. 663 की पूर्व में अपीलान्त व अन्य को कोई पता नहीं था। जब रेस्पोजेन्ट सं. 1 ने भूमि का दायरा बढ़ा मानकर वहा से मकान हटाने हेतु दिनांक 20.11.2024 को कहा तथा ऐलानिया कहा यदि वाद स्थल से मकान नहीं हटाये तो व जेसीबी व इलैक्ट्रीक की मशीनो से तोड़ देंगे। जिस पर पटवारी हल्का से अपीलान्त ने समस्त जानकारी जुटाई है तथा बिना किसी देरी किये अपीलाधीन नामान्तरण आदेश की नकल दिनांक 22.11.2024 को प्राप्त की, जो ज्ञान से अन्दर मियाद है तथा अपीलाधीन नामान्तरण से पूर्व अपीलान्त व अन्य पट्टे धारियों



को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई तथा पट्टो को कैंन्सील कराये बगैर गै. मु. सड़क आबादी का निरीक्षण किये व मकानो के स्थान पर दर्ज गैर कानूनी ढंग से किया गया है। इसलिए प्रकरण मेरीटोरियस है, जिस पर कोई मियाद अवधि लागू नहीं होती है फिर भी कानूनी तौर से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जो अन्दर मियाद है।

7. अपील अपीलान्त न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र की है व अन्दर मियाद है तथा मुकरर न्याय शुल्क पर तहरीर कर पेश है।

अतः अपील अपीलान्त प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण आदेश सं. 663 दिनांक 20.11.2009 रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर बअदालत श्रीमान तहसीलदार राजस्व नोहर को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या- 02 से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांत की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांत द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के ख0नं0 444 की 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि गैर मुमकीन आबादी भूमि थी तथा आबादी भूमि में ग्राम वासियों पक्के मकान निर्मित थे तथा ख0नं0 435 में भी आबादी बसी हुई है। उनके पक्ष में पट्टे जारी कर रखे थे तथा सैकड़ों वर्षों की रिहायश थी। केन्द्र सरकार की अनुमती के बिना सड़क निर्मित करना संभव नहीं है। रेस्पोंडेन्टस-2 ने रेस्पोंडेन्ट सं. 1 के पक्ष में बिना की जाँच किये ग्राम पंचायत को बिना सुने नामान्तरण संख्या 663 दिनांक 20.11.2009 तस्दीक किया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। इस हेतु निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये--

1. 2019 RBJ page No. 69
2. 2009(2)RRT page no. 1102
3. 2017(1) RRT page no. 1
4. 2017(2) RRT page No. 1293

अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 663 दिनांक 20.11.2009 को अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता अपीलांत की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पायतन एवं वन विभाग(मरुस्थल वनरोपण एवं चारागाह विकास हेतु आरक्षित भूमि) को सार्वजनिक निर्माण विभाग गै0मु0 सड़क अरड़की से गोरखाना के नाम दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण



प्रकरण संख्या 50/2024 अनवान जयप्रकाश आदि बनाम अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, नोहर

संख्या- 663 दिनांक 20.11.2009 को दर्ज करने उक्त भूमि पर पट्टे शुदा भूखण्ड बसे हुए लोगों को सुनवाई का अवसर नहीं देकर त्रुटि कारित की है।

अतः न्यायालय के मत अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि नामान्तरण संख्या 663 में दर्ज भूमि बसे लोगों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसर प्रकरण का निस्तारण करे।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 19/3/26 को सरेइजलास सुनाया गया।



(सिजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)